''विद्यार्थी जानते हैं कि विश्व ज्ञान समाज की कोई सीमा नहीं है। अब यह सरकार और उच्च शिक्षा संस्थानों पर निर्भर करता है कि वे निजी क्षेत्र के साथ मिलकर किस तरह विद्यार्थियों की आकांक्षा को पूरा कर पाते हैं।''

– अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट, **कैरेन पी. ह्यूज़**
मुंबई, मार्च 2007

एसोसिएटेड प्रेस © पी.टी.-एसोसिएटेड प्रेस

अमेरिका-भारत उच्च शिक्षा

छात्रों और प्रोफ़ेसरों की आवाजाही और शोध कार्य एवं प्रयोगशालाओं में संपर्क बेहतरीन गुणवत्ता की शिक्षा और श्रेष्ठ डिग्रियों की बढ़ती मांग को पूरा कर सकती है।

सेबास्तियन जॉन

अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित जॉर्जिया अपने मीठे आडुओं और व्यस्त हवाई अड्डे के लिए प्रसिद्ध है। उड्डयन, सेलफोन उपकरण और कागज की लुग्दी यहां के महत्वपूर्ण निर्यात उद्योग हैं। आगामी वर्षों में भारत के साथ बढ़ते व्यापार की संभावना को देखते हुए यह राज्य केवल व्यापार प्रतिनिधिमंडलों और मार्केटिंग कार्यालयों पर पैसा खर्च नहीं कर रहा बल्कि अध्यापकों की तलाश में जुटा है और हैदराबाद, आंध्रप्रदेश में एक आधुनिकतम शोध परिसर के निर्माण की आशा कर रहा है।

जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नॉलॉजी(जॉर्जिया टेक) भारत स्थित ऐसा पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय बनना चाहता है जो भारत में ही अपने अटलांटा, अमेरिका स्थित परिसर जैसी ही अमेरिका द्वारा स्वीकृत स्नातक डिग्री उपलब्ध करवाए। जॉर्जिया टेक के प्रोवोस्ट डॉ.गैरी बी. शूस्टर कहते हैं कि हैदराबाद परिसर उन क्षेत्रों पर प्रयास केंद्रित करेगा जो भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं लेकिन अमेरिकी आर्थिक हितों के लिए भी अवसर प्रदान करेंगे। इस परिसर के नियोजक शोध सुविधाएं स्थापित करने और अन्य प्रकार के सहयोगों के लिए कंपनियों से चर्चा कर रहे हैं। बिजली वितरण, सौर ऊर्जा और आधारभूत ढांचा अभियांत्रिकी जैसे रोचक और सामाजिक रूप से संगत पाठ्यक्रमों के छात्रों को जॉर्जिया टेक का स्थायी अध्यापक वर्ग पढ़ाएगा और 5 जून 2007 को विश्वविद्यालय और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र के अनुसार उन्हें अमेरिका में पढ़ने का अवसर भी मिलेगा। डॉ.शूस्टर बताते हैं कि भारत में एक वर्ष में 500 से भी कम छात्र विज्ञान/प्रौद्योगिकी में डॉक्टरेट की उपाधि लेते हैं। हमारे पाठ्यक्रमों का उद्देश्य ऐसे छात्र तैयार करना होगा जो सफल उद्यमी भी हों। इस तरह हम भारत में रोज़गार तलाश रहे लोगों की नहीं, नए रोज़गारों और उद्योगों की संख्या बढ़ाएंगे।

साभार: ए. महेश कुमार

ऊपर: बेंगलूर, कर्नाटक में वर्ष 2006 में लिंडन अमेरिकी विश्वविद्यालय मेले में भारतीय विद्यार्थी मेले में शामिल 32 अमेरिकी विश्वविद्यालयों में से कुछ के बारे में जानकारी पढ़ते हुए।

बाएं: जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी के प्रोवोस्ट गैरी बी. शूस्टर जून 2007 में आंध्र प्रदेश सरकार के अधिकारियों के साथ सहमति पत्र का आदान-प्रदान करते हुए: (बाएं से दाएं) मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी, तकनीकी शिक्षा मंत्री आर. चेंगा रेड्डी और उच्च शिक्षा के प्रधान सचिव सी.बी.एस. वेंकटरमन।

जॉर्जिया टेक शिक्षा में एक नए भारत-अमेरिकी सहयोग में अग्रगामी बनना चाहता है लेकिन ऐसा करने वाला वह अकेला संस्थान नहीं है। अब जब भारतीय मंत्रिमंडल विदेशी शिक्षा संस्थान विधेयक पर विचार कर रहा है और राष्ट्रपति बुश और अमेरिकी विदेश विभाग ने विदेशी विश्वविद्यालयों से सहयोग की पहल की है, अमेरिकी उच्च शिक्षा संस्थान भारत में स्थापित होने के अनूठे उपाय ढूंढ रहे हैं। विचाराधीन भारतीय कानून भारत में शैक्षिक परिसर स्थापित करने के लिए नियम स्पष्ट करेगा। इस विधेयक का एक प्रस्तावित प्रावधान यह है कि विदेशी संस्थान 51 प्रतिशत पूंजी का निवेश करेंगे और ज़्यादातर मामलों में सभी लाभ भारतीय सहयोगी संस्थान में ही निवेशित कर दिए जाएंगे। विदेशी संस्थानों को सुनिश्चित करना होगा कि भारत में चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता उनके स्वदेश स्थित परिसरों जैसी ही हो। परामर्शदाता मंडल से सलाह लेकर सरकार भारतीय आरक्षण, प्रवेश और ट्यूशन नियमों में छूट भी दे सकती है। भारतीय राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार 18 से 24 वर्ष के आयु वर्ग के केवल 7 प्रतिशत युवा

दुतरफा शैक्षणिक आदान-प्रदान

अमेरिका भारतीय छात्रों के लिए अपने द्वार पहले से भी अधिक खोलना चाहता है। हम यह भी चाहते हैं कि अधिक संख्या में अमेरिकी युवा अध्ययन के लिए भारत आएं। छात्रों के द्विपक्षीय आदान-प्रदान से भारत में:

- शिक्षा की मांग को पूरा करने में सहायता मिलेगी क्योंकि यहां उच्च शिक्षा के इच्छुक छात्रों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में पर्याप्त स्थान नहीं हैं।
- अमेरिकी परिसरों में भारतीय प्रतिभा और रचनात्मकता का प्रवाह बना रहेगा।
- अमेरिकी छात्रों को वैश्विक वातावरण में प्रभावी ढंग से काम करने का महत्वपूर्ण कौशल मिलेगा और वे भारतीय संस्थानों को अपने बौद्धिक सहयोग से समृद्ध बनाएंगे।
- अमेरिकी और भारतीय व्यवसायों की कुशल, जानकार कामगारों की बढ़ती मांग पूरी हो पाएगी।
- हमारे देशों के बीच मजबूत सम्बन्ध रचने में भावी पीढ़ियों को सहायता मिलेगी।

अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट,
कैरेन पी. ह्यूज,
मुंबई, 26 मार्च, 2007

यूएस इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिएन अंडरग्रेजुएट लीडर्स प्रोग्राम की हिबा अलीम यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेंपरेरी अमेरिकन लिट्रेचर से अध्ययन करने वालीं निशि पांडे के साथ अमेरिका की अंडर सेक्रेटेरी ऑफ़ स्टेट कैरेन पी. ह्यूज़ का स्वागत करती हुईं।

विश्वविद्यालयों में दाखिला लेते हैं, ऐसे में शैक्षणिक अवसर बढ़ाना 21वीं सदी में भारत के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में शिक्षा अमेरिकी छात्रों और अमेरिकी सरकार की भी प्राथमिकता है।

पूर्व का आकर्षण

विदेश में अध्ययन प्रतिस्पर्धापूर्ण वैश्विक वातावरण में सफलता का अति आवश्यक घटक बनता जा रहा है। मार्च में भारत आने पर अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट कैरेन पी. ह्यूज़ ने कहा कि आज का छात्र समझता है कि वैश्विक ज्ञान समाज असीम है। अब निजी क्षेत्र के सहयोग से सरकार और उच्च शिक्षा संस्थानों को छात्रों की महत्वाकांक्षा पर खरा उतरने की चुनौती पूरी करनी है। उनके प्रतिनिधिमंडल में अमेरिकी कम्युनिटी कॉलेजों के अध्यक्ष भी शामिल थे (इन कॉलेजों की डिग्रियां चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थानों में मान्य हैं) अंतरराष्ट्रीय अनुभव प्राप्त करने के लिए अपने छात्रों को भारत भेजने के लिए भारतीय संस्थाओं से साझेदारी करने वाले संस्थानों में न्यू यॉर्क सिटी की कोलम्बिया यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन डी.सी. की जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ़ नॉर्थ डकोटा भी शामिल हैं। अमेरिकी सरकार अमेरिका-भारत कृषि ज्ञान पहल जैसे शैक्षणिक सहयोगों को भी पोषित कर रही है जिनमें दोनों देशों के छात्रों को साझे डिग्री पाठ्यक्रम करने देने का प्रावधान है। अमेरिकन सोसायटी ऑफ़ इंजीनियरिंग एजुकेशन भारतीय अभियांत्रिकी शिक्षाविदों के साथ मिलकर अभियांत्रिकी शिक्षा को सुधारने की योजना पर कार्य कर रही है, हाल ही में इन्फोसिस के बेंगलूर परिसर में दोनों पक्षों की

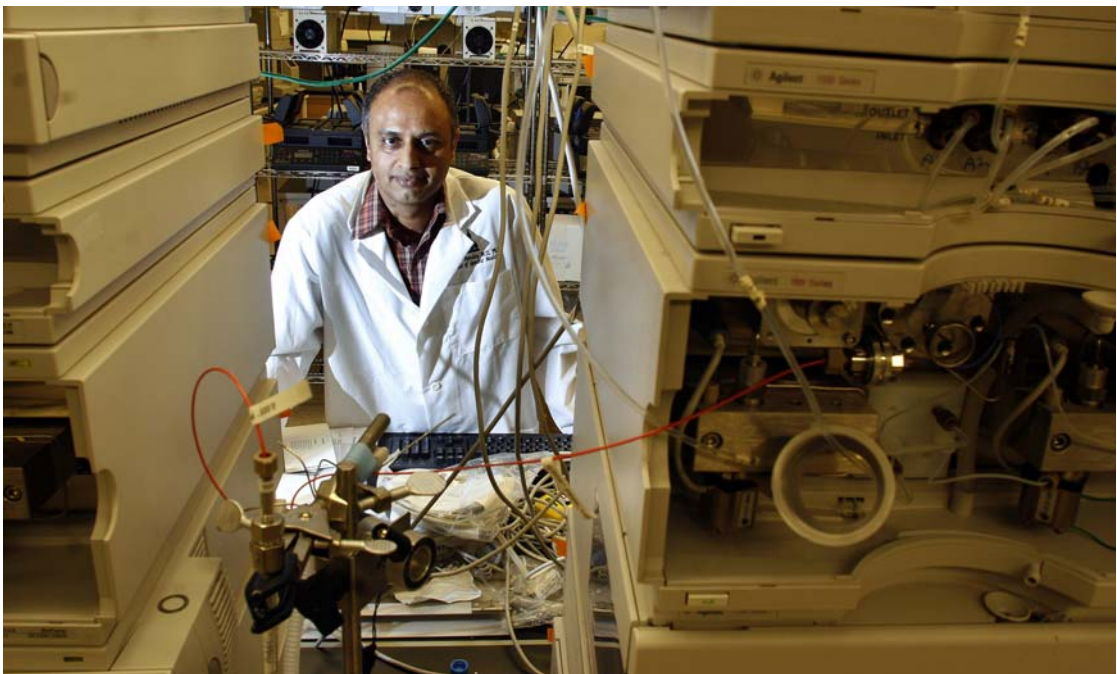

बाल्टीमोर, मैरीलैंड की जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी में अपनी प्रयोगशाला में अखिलेश पांडे। वह बेंगलूर, कर्नाटक के शोधकर्मियों के साथ भी संपर्क में रहते हैं।

विकास फलला

एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। लिंडन टूअर्स के डैरिल कैल्किन्स शैक्षणिक मेलों का आयोजन करते हैं जहां अमेरिकी विश्वविद्यालयों के पदाधिकारी भावी भारतीय छात्रों से मिल सकते हैं। वह कहते हैं कि भारत को लेकर तैयार हुआ यह आग्रह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती जागरूकता और अमेरिका में सम्भावित छात्रों की मांगों को पूरा करने को लेकर अमेरिकी विश्वविद्यालयों के सरोकार के कारण है। विदेशों में संयुक्त पाठ्यक्रम और परिसर खोलकर वे उन छात्रों को उनके ही देश में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध करवा सकते हैं जो वरना अमेरिकी परिसर में पहुंचते। कैल्किन्स का कहना है कि अमेरिकी विश्वविद्यालय समझ गए हैं कि तेज़ी से वैश्वीकृत होते संसार में उन्हें और अधिक अमेरिकी छात्रों को अध्ययन करने और परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए विदेश भेजना होगा। भारत में चलने वाले पाठ्यक्रम छात्रों को एक सुपरिचित सा वातावरण उपलब्ध करवाते हैं। और नए गठबन्धन रचने में सिर्फ परम्परागत विश्वविद्यालयों की ही रुचि नहीं है- बोस्टन, मैसाच्यूसेट्स का सिमन्स स्कूल ऑफ़ मैनेजमेंट कोलकाता के इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट के साथ छात्र आदान-प्रदान कार्यक्रम शुरू कर रहा है ताकि दोनों संस्थानों के छात्र वैश्विक अनुभव पा सकें और विशेष रूप से छात्राओं को उद्यमी बनने के लिए नेतृत्व की भूमिका के अवसर मिल सकें। सिमन्स की डीन डेबॅरा मेरिल-सैंड्स कहती हैं, ''मेरा दृढ़ विश्वास है कि आज एक संगठन में सफल व्यवस्थापक के लिए वैश्विक अनुभव और अंतर्सांस्कृतिक दक्षताएं जरूरी हैं।''

जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अखिलेश पांडे ने कैंसर से लड़ने में सहायता के लिए प्रोटीनों को पृथक करने और उनके अध्ययन से जुड़े अपने प्रयोगों के परिणामस्वरूप तैयार हुए ढेरों आंकड़ों के मूल्यांकन के लिए 2002 में बेंगलूर में इंस्टिट्यूट ऑफ़ बायोइन्फॉर्मेटिक्स की स्थापना की। कई लोगों को उनकी सफलता संदिग्ध लगती थी। प्रो.पांडे ने अपने पैसों से संस्थान की स्थापना की, उन्हें अनुदान तो बाद में मिले। आज यह संस्थान ह्यूमन प्रोटीन रेफरेंस डेटाबेस संचालित करता है जिसमें 24,000 से ज़्यादा मानवीय प्रोटीनों पर सूचना संकलित है। संसारभर की प्रयोगशालाएं इस डेटाबेस से सूचना प्राप्त करती हैं। प्रो. पांडे ने संस्थान के कई बेंगलूर स्थित शोधकर्ताओं को भारत में पीएच. डी. पूरी करके मैरीलैंड सिथत जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने में सहायता दी है। उन्हें आशा है कि वह भारत में कम कीमत पर काम कर पाने की सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक अन्य अमेरिकी संस्थानों के साथ भी सहयोगी परियोजनाएं चला पाएंगे। सहयोगी परियोजनाओं में निजी कंपनियों की भी बड़ी भूमिका रहती है। क्वालकॉम, माइक्रोसॉफ़्ट और केडेन्स डिज़ाइन सिस्टम्स से मिलने वाले अनुदानों के कारण यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैलिफोर्निया, बर्कली, कार्नेगी मेलॅन यूनिवर्सिटी और कॉर्नेल सहित कई अमेरिकी विश्वविद्यालयों के लिए तमिलनाडु में अमृता यूनिवर्सिटी के साथ एक विज्ञान और अभियांत्रिक इलेक्ट्रॉनिकी - शिक्षण कार्यक्रम शुरू करना सम्भव हो पाया है।

सेबास्टियन जॉन

पश्चिम का आकर्षण

भारत में ही अमेरिकी शिक्षा प्राप्त करने के बढ़ते अवसरों के बावजूद अमेरिका में ही पढ़ने की इच्छा में कमी नहीं आ पाई है। भारतीय राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का अनुमान है कि विदेश में पढ़ रहे

फोटो: साभार वाशिंगटन यूनिवर्सिटी

अंतरराष्ट्रीय अध्येताओं की खोज

बहुराष्ट्रीय निगम सेंट लुई, मिजूरी में वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में स्थापित की जा रही मैक्डॉनेल इंटरनेशनल स्कॉलर्स एकेडमी के लिए वित्तीय संसाधन जुटा रहे हैं। इसमें प्रमुख एशियाई विश्वविद्यालय भागीदारी कर रहे हैं जिनमें मुंबई स्थित इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी और नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शामिल हैं। वर्ष 2006 के शरत सत्र के लिए आए अंतरराष्ट्रीय अध्येताओं के पहले दल में तीन भारतीय अध्येता भी थे। शोधकार्य के दौरान उन्हें यात्रा, ट्यूशन और खाने-रहने का खर्च उपलब्ध करवाया जाता है। एकेडमी ने आदान-प्रदान कार्यक्रम को मज़बूत बनाने के लिए एक सद्भावना दूत भी नियुक्त किया है। 1984 में अमेरिका में बस गए और कोलकाता में जन्मे हिमाद्रि बी. पकड़ाशी आईआईटी मुम्बई के लिए एकेडमी के दूत हैं। वह वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के नए इंटरनेशनल सेंटर फॉर एडवांस्ड रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी के निदेशक भी हैं।

वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के चांसलर मार्क एस.राइटन ने फरवरी 2007 में भारत के राजनीतिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक क्षेत्र के अग्रणी लोगों से मिलकर शिक्षा और शोध के और क्षेत्रों की पहचान की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने कहा, ''शुरुआत ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्रों से होगी। हमने किसी तरह के विरोध का सामना नहीं किया। हमें उन क्षेत्रों की पहचान करनी होगी जिनमें सहयोग हमारे अध्यापक वर्ग और छात्रों और आईआईटी के अध्यापक वर्ग और छात्रों के लिए अर्थपूर्ण सिद्ध होगा। हमें लगता है कि जैव-ऊर्जा के क्षेत्र में काफी अवसर मौजूद हैं। अमेरिका में शिक्षा और शोध का चोली-दामन का साथ है। हम एक ऐसा दल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके सदस्य संसारभर में नेतृत्व करेंगे। हम इस साझेदारी को द्विपक्षीय स्वरूप में देखते हैं। **- लॉ.की.लौं.**

सबसे ऊपर: वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के चांसलर मार्क एस. राइटन मैक्डॉनल इंटरनेशनल स्कॉलर्स एकेडमी के तहत सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2006 में भारत आए थे। उसी दौरान वह ग्रेजुएट हर्ष और नुपुर अग्रवाल से बातचीत करते हुए।

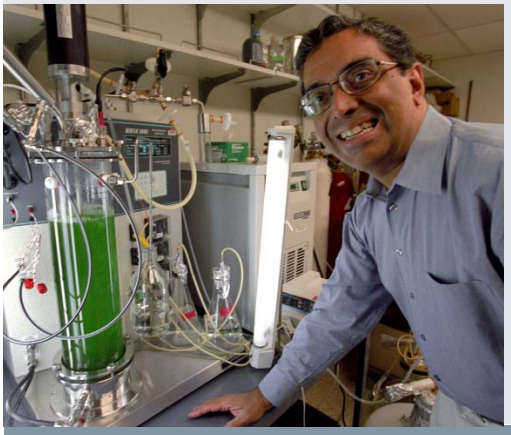

बाएं: मैक्डॉनल इंटरनेशनल स्कॉलर्स एकेडमी के हिमाद्रि बी. पकड़ासी अपनी ऊर्जा प्रयोगशाला में। वह आईआईटी, मुंबई के लिए संपर्क बनाने का काम करते हैं।

कम्युनिटी कॉलेज हैं न !

अगर आपके पास पैसा सीमित है या पहले कभी अंक कम आए हैं तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है – कम्युनिटी कॉलेज हैं न!

कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली क्षेत्र के फुटहिल कॉलेज में अंतरराष्ट्रीय शिक्षा के डीन जॉर्ज बीयर्स पिछले पांच सालों से भारतीय छात्रों को कम्युनिटी कॉलेज की अनूठी अमेरिकी अवधारणा से परिचित करवा रहे हैं।

वह बताते हैं, ''हम पहले दो वर्षों की पढ़ाई का वैकल्पिक साधन हैं।'' कम्युनिटी कॉलेज अक्सर सार्वजनिक वित्तीय संसाधनों पर निर्भर होते हैं। इनके पाठ्यक्रम दो वर्ष के होते हैं और यह देशभर के छोटे कस्बों और बड़े शहरों में मौजूद हैं। यहां दाखिले की प्रक्रिया आसान है और ट्यूशन फीस भी कम है। इसका परिणाम यह है कि कम्युनिटी कॉलेजों के परिसरों में अमेरिका की बहुरंगी संस्कृति की छटा दिखती है- सभी आयुवर्गों, जातीय और सांस्कृतिक परम्पराओं और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग वहां मिलते हैं। अमेरिका में 1202 कम्युनिटी कॉलेजों में 1.16 करोड़ छात्र शिक्षा पा रहे हैं।

विदेशी छात्रों को कम्यूनिटी कॉलेजों में पढ़ने को प्रेरित करने की अमेरिकी पहल के अंतर्गत मार्च 2007 में 16 अमेरिकी कम्युनिटी कॉलेजों के प्रेसिडेंट छात्रों के आदान-प्रदान की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए भारत आए थे। पहले इन कॉलेजों में अध्ययन के लिए जाने वाले छात्रों को वीज़ा मिलने में कठिनाई होती थी लेकिन अब विदेश विभाग कम्युनिटी कॉलेजों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और छात्रों को इस विकल्प को अपनाने को प्रेरित करने का प्रयास कर रहा है।

यूसेफी से हाल ही में सेवानिवृत हुई सलाहकार विजया खंडाविली कहती हैं, ''मुझे लगता है कि कम्युनिटी कॉलेज भारतीय छात्रों के लिए किफायती विकल्प हैं। दो साल वहां पढ़ने के बाद छात्र चार साल के पाठ्यक्रम वाले कॉलेजों में दाखिला ले सकते हैं।''

सार्वजनिक कम्युनिटी कॉलेजों में फीस वगैरह का खर्चा औसतन चार साल के पाठ्यक्रम वाले सार्वजनिक कॉलेजों की तुलना में आधे से कम और निजी चार साल के पाठ्यक्रम वाले कॉलेजों की तुलना में कुल दस प्रतिशत ही होता है।

विजया खंडाविली कहती हैं कि कम्युनिटी कॉलेजों की अपेक्षाकृत कम छात्र संख्या वाली कक्षाओं में भारतीय छात्र आसानी से तालमेल बैठा पाते हैं। साथ ही यहां पढ़ते हुए छात्र 'अमेरिकी समाज और लोगों को भी बेहतर ढंग से समझ पाते हैं।

जॉर्ज बीयर्स ध्यान दिलाते हैं कि उनके कॉलेज में प्रोफेसर कक्षाएं लेते हैं, उनके सहायक नहीं। और उन्हें गर्व है कि उनके यहां पढ़ने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों को बाद में ऊंचे नामों वाले यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैलिफोर्निया, येल और स्टैनफोर्ड जैसे कॉलेजों में दाखिला मिलता है।

कम्युनिटी कॉलेजों से आए छात्रों के हाईस्कूल में मिले अंकों की चिंता नहीं की जाती। केवल कम्युनिटी कॉलेजों में हुए शैक्षणिक मूल्यांकन पर ध्यान दिया जाता है। वह कहते हैं, ''यह जैसे किसी नामी विश्वविद्यालय में दाखिला पाने के लिए बढ़िया शैक्षणिक प्रदर्शन दिखाने का एक अतिरिक्त अवसर है।

अधिक सूचना के लिए अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ़ कम्युनिटी कॉलेजेज की वेबसाइट देखें: http://www.aacc.nche.edu/

–से. जॉ.

बेंगलूर, कर्नाटक में लिंडन अमेरिकी विश्वविद्यालय मेले में कैलिफ़ोर्निया के फुटहिल कॉलेज के अंतरराष्ट्रीय शिक्षा के डीन जॉर्ज बीयर्स विद्यार्थियों से बातचीत करते हुए।

एजाज़ ग़नी © ए. पी. – डब्ल्यू. डब्ल्यू. पी.

करीब 160,000 भारतीय हर वर्ष लगभग 4 अरब डॉलर खर्च कर रहे हैं। 2006 में 76,500 से अधिक भारतीय शिक्षा के लिए अमेरिका गए। यूसेफी से हाल ही में सेवानिवृत्त हुई सलाहकार विजया खंडाविली कहती हैं, ''अधिकांश भारतीय छात्र स्नातकोत्तर और डॉक्टरल अध्ययन के लिए अमेरिका जाते हैं लेकिन अब करीब 20 प्रतिशत स्नातक अध्ययन के लिए भी जाते हैं। भारतीय शिक्षार्थियों को वीजा प्रक्रिया से लेकर उनकी आवश्यकता के हिसाब से सबसे सही संस्थान के चुनाव, ठिकाना ढूंढने, आवेदन पत्र भरने से लेकर अकादमिक कार्य के लिए विश्वविद्यालय के क्रेडिट प्राप्त करने तक की सांस्कृतिक स्तर पर सामंजस्य बैठाने से जुड़ी समस्याओं को हल करने में यूसेफी भारतीय शिक्षार्थियों की सहायता करती है।'' वह गोष्ठियों, कार्यशालाओं और संवादों के माध्यम से अमेरिका से शिक्षा पाकर लौटे भारतीयों और अमेरिकियों से मिलवाती हैं। टेक्सास ए एंड एम यू में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएच. डी. कर रहे दीपक गोयल 2001 से अमेरिका में पढ़ रहे हैं। अमेरिका में अपने पहले वर्ष के बारे में बताते हुए वह कहते हैं, ''शुरू में तो तमाम भारतीय छात्रों की ही तरह मैं उत्साह से भरा था, मुझे नई सम्भावनाएं दिख रही थीं, लेकिन बाद में अमेरिकी प्रणाली थकाऊ और उलझन भरी लगने लगी। मेरे कुछ साथी तो परेशान हो कर लौट भी गए। कुछ हद तक सभी इस अनुभव से गुजरते हैं। अक्सर भारतीय छात्रों के मन में अमेरिका का एक बिम्ब होता है- जब वह वास्तविकता से मेल नहीं खाता तो परेशानी होती है।'' वह बताते हैं कि खुद खाना बनाना और परिवार और मित्रों का न होना उन्हें बहुत भारी लगता था। नए पाठ्यक्रम अपनाकर और प्रोफेसरों से बातचीत करके इस समस्या को हल किया जा सकता है। खुद उन्होंने अध्ययन के अपने मुख्य क्षेत्र से बाहर जाकर अर्थशास्त्र और बॉलरूम डांस जैसे विषय पढ़े। उन्हें कक्षा में बहस के अवसर भी पसन्द आए। वह कहते हैं, ''अगर आप अपने शिक्षक से सहमत नहीं हैं तो खुलकर अपनी बात कर सकते हैं, एक शिक्षक आपके परीक्षा परिणाम या जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएगा।'' विजया खंडाविली चेताती हैं कि छात्रवृति मिलने के बावजूद भारतीय छात्रों को औसतन हर वर्ष 20,000 डॉलर की ज़रूरत होती है, भारत में ही अमेरिकी शिक्षा प्राप्त करने का यह भी एक बड़ा कारण है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मई 2007 में अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस.राजशेखर रेड्डी ने कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और सत्यम कम्प्यूटर्स इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट के साथ भारतीय आपातकालीन चिकत्सा सहायकों या पैरामेडिक्स की शिक्षा के लिए हैदराबाद में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शाखा परिसर की स्थापना के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। कोलम्बिया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ़ जर्नलिज्म के डीन ऑफ़ स्टूडेंट्स और एसोसिएट प्रोफेसर श्रीनाथ श्रीनिवासन कहते हैं कि अमेरिकी विश्वविद्यालयों को अपने कामकाज और अपने यहां मौजूद भारतीय छात्रों के बारे में भारत में और अधिक प्रचार करना चाहिए। हाल ही में अपनी दक्षिण भारत की यात्रा में उन्हें बहुत ही सम्भावित छात्र मिले जिन्होंने अमेरिकी शिक्षा प्रणाली के बारे में काफी खोजबीन की थी और भारतीय पूर्व छात्रों से भी जानकारियां इकट्ठी की थीं। विजया खंडाविली बताती हैं, ''भारतीय संस्थान वर्ष के आधार पर पढ़ाते हैं जबकि अमेरिकी संस्थान सेमेस्टर पद्धति का अनुसरण करते हैं। इस स्थिति में शैक्षणिक क्रेडिट नियत करने में कठिनाई आती है।'' कुछ संस्थानों ने इस समस्या का समाधान ट्विनिंग करके किया जिस में छात्र कुछ वर्ष भारत में पढ़ते हैं और फिर

सावधान रहें

वीज़ा घपले!

पीटर जी. केस्नर
अमेरिकी दूतावास के कान्सुल जनरल

आपको वीज़ा एजेंट की ज़रूरत नहीं है और आप ऐसे किसी व्यक्ति को एक पैसा न दें जो आपको शर्तिया वीज़ा दिलवाने की बात कह रहा हो। हमारी वीज़ा खिड़की पर रोज़ ही कुछ योग्य वीज़ा आवेदकों को इसलिए वीज़ा देने से मना कर दिया जाता है क्योंकि उन्होंने 'वीज़ा कंसल्टेंट' या 'दोस्तों' की राय पर वाइस कान्सुल के समक्ष जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए। इसके अलावा दलाल वीज़ा प्रणाली का दुरुपयोग करते हैं और अपने ग्राहकों को नुकसान पहुंचाते हैं। वे अपॉइंटमेंट लेकर उन्हें बेच देते हैं।

मैं महसूस करता हूं कि भारत में इन 'कंसल्टेंट' के फलने-फूलने का कारण यह है कि भारत के लोगों तक उपयोगी सूचना पहुंचाने में अमेरिकी सरकार उतनी प्रभावी नहीं रही है जितना वह हो सकती है। सूचना की इस खाई के चलते कंसल्टेंटों को फलने-फूलने का मौका मिल गया। अमेरिकी दूतावास ने हमारे वीज़ा नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं के बारे में भारतीयों को बेहतर ढंग से सूचित करने के प्रयास फिर से तेज़ किए हैं। भारतीय आवेदक यूसेफी और अमेरिकी दूतावास जैसे विश्वस्त स्रोतों से निःशुल्क सही सूचना प्राप्त करें, यह बहुत महत्वपूर्ण है।

http://newdelhi.usembassy.gov/visa_services.html

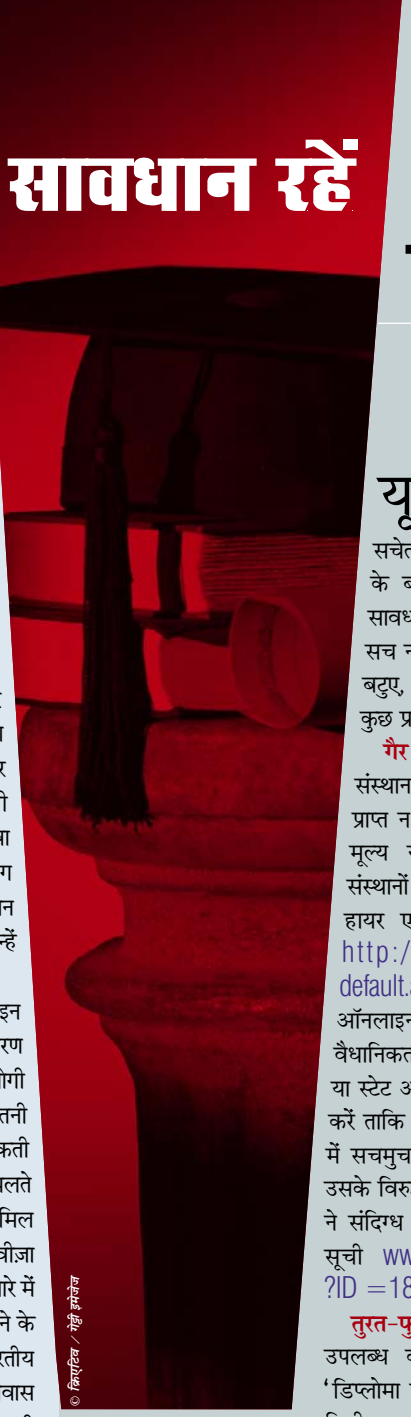

© किशोरिव / पॉप्पी इमेजेज

शिक्षा घपले!

जेन ई. शुकॉस्के
यूसेफी की कार्यकारी निदेशक

यू.एस. एजुकेशनल फ़ाउंडेशन इन इंडिया (यूसेफ़ी) भारतीय छात्रों को सचेत करता है कि वे अमेरिकी उच्च शिक्षा के बारे में ऐसे विज्ञापनों और दावों से सावधान रहें जो बेहद लुभावने होते हैं लेकिन सच नहीं होते। घोटाले आपकी प्रतिष्ठा और बटुए, दोनों को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ प्रचलित शिक्षा घोटाले हैं :

गैर मान्यता प्राप्त संस्थान : अगर संस्थान किसी अधिकारिक एजेंसी से मान्यता प्राप्त न हो तो उसके दी गई डिग्री का कोई मूल्य नहीं होगा। छात्र अमेरिकी शिक्षा संस्थानों की मान्यता का स्तर काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन एक्रेडिटेशन की वेबसाइट http://www.chea.org/search/default.asp पर जांच सकते हैं। किसी ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा संस्थान की वैधानिकता जानने के लिए बेटर बिज़नेस ब्यूरो या स्टेट अटॉर्नी जनरल के कार्यालय से सम्पर्क करें ताकि पता चल सके कि संस्थान उस राज्य में सचमुच वैधानिक रूप से चल रहा है और उसके विरुद्ध शिकायतें दर्ज हुई हैं या नहीं। ब्यूरो ने संदिग्ध ऑन लाइन शैक्षणिक कार्यक्रमों की सूची www.bbb.org/alerts/article.asp?ID =185 पर उपलब्ध करवाई है।

तुरत-फुरत डिग्रियां : तुरत-फुरत डिग्रियां उपलब्ध करवाने वाले संस्थानों को अक्सर 'डिप्लोमा मिलें' भी कहा जाता है। एक जाली डिग्री आपकी प्रतिष्ठा को धूल में मिला सकती है। आप काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन एक्रेडिटेशन की वेबसाइट www.chea.org/pdf/fact_sheet_6_diploma_mills.pdf पर संदिग्ध संस्थानों की जांच कर सकते हैं।

जाली विज्ञापन : इनके कुछ नमूने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट http://www.ugc.ac.in/inside/malprac.html पर भी उपलब्ध हैं।

हाथोंहाथ प्रवेश : अमेरिका में अच्छे शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला शिक्षकों की एक समिति द्वारा आवेदक के शैक्षणिक रिकॉर्ड, परीक्षा में प्राप्त अंकों, रेफरेंस और निजी बयान की समीक्षा के आधार पर होता है। 'हाथोंहाथ दाखिले' से लगता है कि किसी को भी दाखिला मिल जाएगा। ऐसे में संस्थान और शिक्षा की गुणवत्ता पर संदेह होना सहज ही है। ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिकी वीज़ा के लिए आपके आवेदन की जांच करने वालों को आपके गम्भीर छात्र होने पर ही संदेह हो जाए।

अमेरिकी वीज़ा का वादा : कोई भी संस्थान या एजेंट आपको अमेरिकी वीज़ा मिलने की गारंटी नहीं दे सकता। वीज़ा देना या न देना सिर्फ कोई अमेरिकी कान्सुलर अधिकारी ही तय करता है।

महंगी छात्रवृत्तियां : छात्रवृत्ति दिलवाने की गारंटी देने वाली स्कॉलरशिप सर्विस को अग्रिम फीस न भेजें, कोई भी स्कॉलरशिप सर्विस छात्रवृत्ति नहीं दे सकती। छात्रवृत्तियों की सूचियां आसानी से इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध हैं। अधिक विवरण www.educationusa.state.gov/finaid.htm पर देखें।

अगर कोई भी विज्ञापन इतना लुभावना है कि यकीन नहीं होता कि वह सच है तो शायद वह सचमुच झूठ ही हो। अपनी प्रतिष्ठा और शिक्षा की कद्र करें। अपने पैसों को समझदारी से खर्च करें। सावधान रहें और शिक्षा घोटालों से बचें।

http://www.fulbright-india.org/

पढ़ाई पूरी करने अमेरिका जाते हैं। यह पद्धति 1990 के दशक में कर्नाटक की मणिपाल एकेडमी और यूनिवर्सिटी ऑफ ओहायो ने शुरू की थी। लेकिन विजया सावधान करती हैं कि छात्रों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि भारत में की गई उनकी पढ़ाई को अमेरिकी विश्वविद्यालय सचमुच स्वीकार कर लेंगे। इसमें बाधाएं हो सकती हैं लेकिन छात्रों को पता होना चाहिए कि यह किया जा सकता है। पिट्सबर्ग, पेन्सिलवैनिया की कार्नेगी मेलॅन यूनिवर्सिटी के मास्टर्स ऑफ़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कार्यक्रम के सहयोगी निदेशक मेल रॉसॉ-लोपार्ट बताते हैं कि तमिलनाडु के एसएसएन कॉलेज के आदान-प्रदान के अंतर्गत उनके यहां पढ़ने वाले भारतीय छात्र हमेशा अपने अमेरिकी सहपाठियों के साथ स्पर्धा में खरे उतरते हैं। वह कहते हैं कि अमेरिकी छात्रों को याद रखना होगा कि भारतीयों के मन में ज्ञान के लिए सम्मान और सफल होने की इच्छा उन्हें अन्य छात्रों की तुलना में कुछ अलग बनाती है।

__सेबास्तियन जॉन__ भारतीय लेखक एवं फोटोग्राफर हैं और वाशिंगटन, डी.सी. में रहते हैं।

इस लेख के बारे में अपने विचार editorspan@state.gov पर भेजिए।